

समझौते की सार्थकता

विश्वायापी जलवायु संकट के बीच दुर्बुद्ध में आयोजित जलवायु परिवर्तन कोदित सीओपी-28 में भले ही कोई क्रांतिकारी फैसला ग्लोबल वार्मिंग तापमान को नियंत्रण के बाबत न लिया जा सका हो, लेकिन दुनिया के लगभग दो सौ देश जीवाश्म ईंधन, मसलन कोयले, तेल और गैस का इस्तेमाल धीरे-धीरे खत्म करने पर जरूर राजी हुए हैं। हालांकि, अभी भी तमाम विकासशील देशों में कई तरह की चिंताएं हैं कि समझौते के व्यापक प्रावधान क्या होंगे और उनकी अर्थिक विकास में आने वाली बाधाओं का मुकाबला कैसे होगा। लेकिन इसके बावजूद सम्मेलन में किसी मुद्रे पर सहमति बनाना एक उम्मीद जरूर जगाती है। कुछ देश उम्मीद लगाए बैठे थे कि जीवाश्म ईंधन के उपयोग को खत्म करने के लिए किसी समयबद्ध कार्यक्रम की रूपरेखा तय होगी। वे इस बदलाव की राह में आगे बढ़ाने के बायद से संयुष्ट नजर नहीं आए। विडंबना यह है कि संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित इस जलवायु सम्मेलन में जीवाश्म ईंधन को खत्म करने का विरोध ओपेक देशों के सदस्य ही कर रहे थे। वैसे भी जीवाश्म ईंधन से अर्थव्यवस्था व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति चलाने वाले देशों से ज्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती। इसके विपरीत तेल उत्पादक देश कार्बन जमा करने की तकनीकों को बढ़ावा देने पर बल देते रहे। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उम्मीद थी कि दुनिया के संपन्न देश जीवाश्म ईंधन समाप्त करने के वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व करें, लेकिन वैसा होता नजर नहीं आया। इसकी वजह यह थी कि ताकतवर राष्ट्रों ने दुनिया के प्राकृतिक संसाधनों का जमकर दोहन करके अपना औद्योगिकीकरण किया। निस्सदैह, उसकी ग्लोबल वार्मिंग में बड़ी भूमिका रही है। जब विकासशील देशों के विकास ने गति पकड़ी तो उन्हें पर्यावरण संकट पर जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने से रोका जाने लगा। ऐसे समय पर जब पश्चिमी देश पहले ही अपने जीवाश्म ईंधन का अधिकतम उपयोग कर चुके हैं, विकासशील देशों के साथ बाधकारी शर्तें अन्यायपूर्ण ही कही जाएंगी। दरअसल, इस समस्या का एक पहलू यह भी है कि क्षतिपूर्ति के तौर पर विकसित देश विकासशील देशों को पर्यास वित्तीय सहायता देने को राजी नहीं हुए हैं। तीसरी दुनिया के देश जीवाश्म ईंधन के विकल्प में जिस नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करें, उसके संबल को दी जाने वाली रकम बहेत हम हैं। इसके लिये सत्तर करोड़ डॉलर का फंड नाकामी है। निस्सदैह, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने की लड़ाई में दुनिया के गरीब मुल्कों को बड़ी पूँजी की जरूरत होगी। कहा जा सकता है कि दुर्बुद्ध में संपन्न पर्यावरण सम्मेलन उन लक्ष्यों तक नहीं पहुंचा है, जहां तक पहुंचने की उम्मीद लगाई गई थी। सम्मेलन की सफलता इस बात पर निर्भर करती कि विकासशील व गरीब मुल्कों को नवीकरणीय ऊर्जा के प्रतिस्थापन के लिये कितनी ठोस अर्थिक मदद का प्रावधान किया गया है। साथ ही उन देशों की मदद के लिये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने कोई ठोस प्रयास नहीं किये जो ग्लोबल वार्मिंग के चरम का सामना करते हुए, भयावह अर्थिक संकट से ज़्यादा रहे हैं। दुनिया के तमाम मुल्क बाढ़ व सूखे की त्रासदी झेल रहे हैं। जिनमें उत्तरी पूर्वी अमेरिकी देशों की स्थिति ज्यादा ही खराब है। इनमें कई देश ऐसे हैं जो कई सालों से निरंतर सूखे की भयावह स्थितियों का सामना कर रहे हैं। दरअसल, हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुके ग्लोबल वार्मिंग संकट के मुकाबले के लिये विकसित देशों व दुनिया की वैज्ञानिक बिरादरी को ठोस प्रयास करने की जरूरत है, ताकि भूख व विस्थापन के संकट का मुकाबला किया जाए। दुनिया की खाद्य शृंखला को बचाने की भी सम्भव जरूरत है। साथ ही उन सस्ती तकनीकों व उपकरणों की जरूरत गरीब मुल्कों को है जो 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग तीन गुना बढ़ाने में सहायक हों। साथ ही ग्लोबल वार्मिंग में बड़ी भूमिका निभाने वाली मीथेन गैस का उत्सर्जन कम करना भी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। यह सुखद है कि तीन दर्जन से अधिक गैस-तेल उत्पादक कंपनियां मीथेन उत्सर्जन कम करने पर सहमत हुई हैं। साथ ही मानवता की रक्षा के लिये ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव से बढ़ने वाली बीमारियों पर नियंत्रण व प्रभावित देशों की मदद की भी जरूरत है।

धुएँ और नारों पर मौन मोदी

बुधवार को भारत के नये संसद भवन में धूसकर धुंआ फैलाने और बाहर नारंगाजी करने के पीछे जो लोग हैं, उनमें से चार को पकड़ लिया गया है तथा कुछ की तलाश जारी है। इनसे पूछताछ से मुख्यतः जो बात सामने आई है, उससे प्रथम दृश्या यही प्रतीत होता है कि उनका मक्सद कोई बड़ी घटना को अंजाम देना नहीं था, वरन् जनता की कतिपय समस्याओं की ओर देश की सबसे बड़ी पंचायत का ध्यान आकृष्ट करना था। यह तो माना जा सकता है कि युवाओं द्वारा अपनी बात को थोड़ा सनसनीखेज तरीके से ज़रूर उठाया गया है, लेकिन इसके बरकस दो बातें सामने आई हैं—पहली तो यह कि करोड़ों रुपयों से निर्मित नये संसद भवन की सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत लचर है; और दूसरी बात है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हमेशा की भाँति चुप्पी। इस हादसे ने साक्षित कर दिया है कि देश के साथ बड़ी से बड़ी बात हो जाये, मोदी अपना मौन ब्रत करतई नहीं तोड़ेंगे। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं वरन् एक हद तक शर्मनाक भी है। नया संसद भवन मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। देश में जब कोविड-19 का भीषण प्रकोप था तथा देश को महामारी से लड़ने के लिये बड़ी धन राशि की आवश्यकता थी, तब इसका निर्माण किया गया था। मोदी खुद इसकी प्रगति देखने आते रहते थे। उस समय इस बात का यह कहकर विरोध हुआ था कि पुराने संसद भवन के रहते, वह भी ठीक-ठाक हालत में होने के बावजूद इस नये भवन को बनवाना एक बड़ी फिजूलखर्ची है। बाद में यह बात साफ होती चली गई कि इसका उद्देश्य पुराने भवन के साथ नथी देश के स्वतंत्रता संग्राम की विरासत को मिटाना है। खासकर, उस भवन पर पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जो सुखद छंव बनी हुई थी, वह मोदी को उनकी विचारधारा के कारण कड़ी धूप सी प्रतीत होती थी। इसी ऋम में उन्होंने नेहरू के शासकीय निवास तीन मूर्ति भवन को भी प्रधानमंत्रियों के संग्रहालय में बदलवा दिया। नेहरू विरोध के अलावा मोदी नये भवन का 2024 के लोकसभा चुनाव के लिये भी इसेमाल करना चाहते हैं। बहरहाल, इस भवन के बारे में दावा किया गया था कि इसकी सुरक्षा बड़ी पुख्ता है। विशेषकर 13 दिसम्बर, 2001 को पुराने भवन पर हुए आतंकी हमले के मद्देनजर इसकी ज़रूरत भी थी। इस भवन के उद्घाटन के अवसर पर बुलाये गये विशेष सत्र को छोड़ दें तो यही इसका नियमित सत्र (शीतकालीन) है, जो अब भी जारी है। पहले ही सत्र में, वह भी ठीक उसी दिन- 22 वर्षों के बाद इसकी सुरक्षा व्यवस्था की पोल कुछ निहत्ये युवाओं ने खोलकर रख दी। उनके कृत्य को करतई समर्थन नहीं मिल रहा है परन्तु इसमें कोई शक नहीं रह जाना चाहिये कि इस भवन की सजावट पर तो खूब ध्यान दिया गया है, लेकिन सुरक्षा की बुनियादी आवश्यकता पूरी तरह से नज़दाज़ की गई है। दो दशक पूर्व हुए हमले में तो जांबाज़ सुरक्षाकर्मियों ने आतंकवादियों को संसद भवन में भुसने तक नहीं दिया था। अबकी एक नहीं दो लोग दर्शक दीर्घ से सदन के बीचों-बीच कूद पड़ते हैं और बाकायदा एक से दूसरी बेंचों को फलांगेन में भी सफल हो जाते हैं।

यूजीसी और एनसीईआरटी का हिन्दू राष्ट्र शैक्षणिक कार्यक्रम

भाजपा सरकार केंद्र में अपनी सत्ता की दूसरी पारी के अंत की ओर है। करीब दस साल की इस अवधि में सरकार ने देश के लगभग सभी संस्थानों और संस्थाओं की दशा और दिशा में जो बदलाव किये हैं, वे सबके सामने हैं। ईडी, आयकर विभाग और सीबीआई ने विपक्षी पार्टियों के खिलाफ वह सब कुछ किया, जो वे कर सकती थीं। कई मौकों पर चुनाव आयोग की भूमिका भी निष्पक्ष नहीं रही है। इस बीच, यूजीसी और एनसीईआरटी शिक्षा प्रणाली और पाठ्यक्रमों में सत्ताधारी दल को सुहाने वाले परिवर्तन करने में व्यस्त रही हैं। नवी शिक्षा नीति (एनईपी) हमारी शिक्षा व्यवस्था के ढांचे और स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन लाने वाली है। सरकार द्वारा नियमित रूप से ऐसे निर्देश जारी किये जा रहे हैं जिनसे विद्यार्थियों के मनो-मस्तिष्क में हिन्दू राष्ट्रवादी विचार और सिद्धांत बिठाये जा सकें। सरकार ने सबसे पहले विद्यार्थियों के आंदोलनों और उनके प्रतिरोध को कमज़ोर करने और उनमें भागीदारी करने वालों को डराने-धमकाने का अभियान शुरू किया। इन आंदोलनों के नेताओं पर राष्ट्रद्वेषी का लेबल चस्पा कर दिया गया। तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रस्तावित किया कि प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के प्रांगण में एक बहुत ऊँचे खम्बे पर राष्ट्रीय ध्वज पहराया जाए। यह भी प्रस्तावित किया गया कि जवाहरलाल नेहरू

ध्विद्यालय (जेन्यू) के कैंपस में सेना
एक टैंक स्थापित किया जाए। वह
लिए क्योंकि वहां के विद्यार्थी ऐसे मसले
रहे थे जो सरकार को पसंद नहीं थे। हाल
इसी तर्ज पर कई निर्देश, आदेश जारी किये
हैं। इनमें से एक यह है कि आरएसएस
प्रचारक और अखिल भारतीय विद्यार्थी
षष्ठ (एवीबीपी) के संस्थापक दत्तजी
देलकर की जन्म शताब्दी को मनाने के
ए एक साल तक चलने वाले आयोजनों
विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित की
ए। एक हिन्दू राष्ट्रवादी को राष्ट्रायक का
दी देने का इस प्रयास का फेकस महाराष्ट्र
कॉलेजों पर है। क्या हिन्दू राष्ट्रवादी नेताओं
हीरा बनाने का यूज़ोसी का यह प्रयास
वत है? क्या हमें उन नायकों को याद नहीं
ना चाहिए जो भारतीय राष्ट्रवाद के हामी
और जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक
कार के खिलाफ संग्राम का नेतृत्व किया
? आरएसएस से जुड़े दिलोकर न तो
धीनता संग्राम का हिस्सा थे और न वही
भारतीय सविधान के मूल्यों में आस्था
तो थे। यूज़ोसी ने एक और सर्कुलर जारी
कहा है कि कॉलेजों में सेल्पी पॉइंट बनाए
ने चाहिए जिनकी पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री
श्री का चित्र हो। कहने की जरूरत नहीं
कहा है कि कॉलेजों में सेल्पी पॉइंट बनाए
यह 2024 के आमचुनाव की तैयारी है।
सी भी प्रजातान्त्रिक देश में ऐसा नहीं होना
हिए। क्या सरकार को किसी भी एक पार्टी



के शीर्ष नेता का प्रचार करना चाहिए? क्या यह प्रजातान्त्रिक मानकों का उल्लंघन नहीं है? प्रजातान्त्रिक और संवैधानिक मूल्यों का इस तरह का खुलमखुला मर्खौल क्या सरकार द्वारा अपनी शक्तियों के घोर दुरुपयोग के श्रेणी में नहीं आता? इससे भी एक कदम आगे बढ़कर, यह निर्देश जारी किया गया है। कक्षा सात से लेकर कक्षा बारह तक विद्यार्थियों को इतिहास के पाठ्यक्रम के भूमिका के रूप में रामायण और महाभारत पढ़ा जाना चाहिए (टाइम्स ऑफ इंडिया, 2 नवम्बर, 2023)। एनसीआरटी के एक्स

पैनल के अनुसार, इससे देश के लोगों में देशभक्ति और स्वाभिमान के भाव जागृत होंगे और वे अपने देश पर गर्व करना सीखेंगे। भारत के ये दो महान महाकाव्य निश्चित तौर पर हमारे पौराणिक साहित्य का हिस्सा हैं। वे उस समय के सामाजिक मूल्यों और मानकों

भारत के विकास के नए सोपान

कॉप 28 ने भले ही टकराव को टाल दिया, पर संघर्ष के बिंदु अनसुलझे रहे

क रवान्द्रन

इसमें कोई आश्वय की बात नहीं है कि कॉप 28 दुर्बल वैसे ही आगे बढ़ा है जैसी की उम्मीद थी। चूंकि सदस्य देश इस बात से जूँझ रहे थे कि जीवाश्म ईंधन के सबसे सर्वेक्षणीय मुद्दे को कैसे औपचारिक रूप दिया जाए और उस पर कैसे ध्यान दिया जाए, इसलिए आम सहभाग बनाने की कोशिश करने के लिए जलवायु शिखर सम्मेलन को निर्धारित सीमा से आगे बढ़ाना पड़ा। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार कॉप 28 ने अंतिम घोषणा के रूप में एक प्रस्तावित पाठ जारी किया है, जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई के द्विसे के रूप में देशों से जीवाश्म ईंधन से दूर जाने का आह्वान करेगा। यह कुछ सबसे मुख्य राज्यों की सफलता का प्रतीक है जिन्होंने जीवाश्म युग को समाप्त करने के संकल्प को दर्शित करने के लिए मजबूत भाषा पर जोर दिया, एक ऐसा लक्ष्य जिसका तेल और कोयला उत्पादक देशों, विशेष रूप से सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा जोरदार विरोध किया जा रहा था। यह टकराव शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता में ही अंतर्निहित था, उस कुर्सी पर आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (एडीएनओसी) के सीईओ बैठे थे। शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष सुल्तान अल जबर की एक टिप्पणी श्कोर्ड विज्ञान नहीं है, जो यह दर्शाता है कि वैश्विक तापन को 1.5 एष्ट तक सीमित करने के लिए जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की आवश्यकता है, जिससे भौंहें तन गई। वह इस हद तक दावा करने लगे कि जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से खत्म करना टिकाऊ नहीं होगा। दरअसल, मुख्य शिखर सम्मेलन से इतर एक महिला-उम्मुख कार्यक्रम में उनके और प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई, जहां उन्होंने कहा कि उंगली उठाने का कोई मतलब नहीं है। ओपेक सदस्य उत्सर्जन को पकड़ने और संग्रहीत करने की प्रौद्योगिकियों के माध्यम से जीवाश्म ईंधन के बजाय करना अत्यधिक महगा है जिस संसाधनों पर केंद्रित हो जाता है। घोषणा की भाषा में फेज आउटप्रोडक्शन का बदलाना। लेकिन अधिकांश देशों से इसे खत्म करना पसंद किया। पर कोयले को चरणबद्ध तरीके संबंधित मुद्दों को उठाया, जिसके कारण यह निकट भविष्य में किसी प्रकार नहीं होगा। नई दिल्ली चाहती थी कि अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित विकासशील देशों को जलवायु आगे बढ़ाने के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता हो, लक्ष्यों और विकासशील देशों आकांक्षाओं के बीच संघर्ष हो पदचिह्न में योगदान देता है। वैश्विक पिछले 30 वर्षों से विजली क्षेत्रों में गिरावट की शुरुआत होगी क्योंकि उत्पादन की लोकप्रियता बढ़ेगी। नयी विजली आपूर्ति से विजली इजाफ़ होने की उम्मीद है, जिसको कोयले का विस्थापन शुरू हो जाएगा। वर्षों में इसमें बढ़ोत्तरी होगी। परिणाम स्वरूप चलने वाली विजली 2024 में मात्र 10,332 टेरावाट घटे (टीडब्ल्यूएच कम से 41 टीडब्ल्यूएच कम सापेक्ष गिरावट है, लेकिन यह 30 संकेत है क्योंकि नवीकरणीय ऊज़ को जारी रखे हुए है। सख्त उत्तर के कारण गैस आपूर्ति के संयोजन के कारण हाल के वर्षों अमेरिका में कोयला क्षमता और निवेश में गिरावट आई है। फिर भी

चर का बढ़वा द कि कार्बन कैप्चर से ध्यान वित्तीय इसका मतलब होगा को फेज डाउन से ने चरणबद्ध तरीके भारत ने कथित तौर से समाप्त करने से बारे में उसने कहा ही समय संभव नहीं चरणबद्ध तरीके से त किये जायें। परिवर्तन लक्ष्यों को समय और वित्तीय रूप है क्योंकि ऐसे गों के लोगों की ता है, जो कार्बन क स्तर पर कोयला पर हावी रहा है, 2024 में ईंधन की के सौर और पवन वीकरणीय ऊर्जा से की मांग में अधिक से अगले साल से बढ़ेगा और आने वाले मस्वरूप, कोयले से मूली रूप से गिरकर च) रह जायेगी, जो यह समझ में एक ने बाली चीजों का अपने विकास पथ सर्जन नीतियों और की प्रचुर उपलब्धता में यूरोप और उत्तरी र समग्र उपयोग में एशिया, मुख्य रूप से चान म स्थाया विकास, न को बढ़ाये रखा है। ऐसी रिश्विजली स्रोतों के तेजी से विधी विस्थापित हो जायेगा, जिप्राणी की शुरुआत होगी, क्षमता में निवेश अगले कुछ कोयला भंडार और आर्थिक के लिए ऊर्जा आपूर्ति को आवश्यकता के कारण, एशिया से अधिक कोयला बिजली उत्पादन क्षमता है। क्षेत्र में कोयला उत्पादन क्षमता के लिए ऊर्जा आपूर्ति को अविवरण संबंधी फैलावों की गति धीमी और अमेरिका जैसे दुनिया भूमि अत्यधिक निर्भर है, कोयले करने के लिए काफी तेजी अर्थव्यवस्था के साथ नवीकरण कर रहे हैं। यूरोप और उत्तरी से कोयला उत्पादन को नवीकरणीय ऊर्जा जैसे स्वच्छ जिससे 1990 के बाद से 200 गीगावॉट से अधिक विवरण मुख्य रूप से सख्त रहा है, जबकि उत्तरी अमेरिका ने उत्पादन को गैस से बदल दिया है जिसके कारण बिजली की एशिया ने पिछले पांच वर्षों में अधिक नवी कोयला क्षमता से अधिक कोयला वर्ष 52 गीगावॉट जुड़ने की में, एशिया 2024 में अर्जेंटीना की क्षमता से अधिक कोयला ८ क्षमता का अधिकांश हिस्सा भारत और इंडोनेशिया का 2027 तक जारी रहने की उम्मीद गति से, जिसके बाद कोयला गिरावट शुरू हो जायेगी।

आज का राशी फल					
मेष	वृष	मिथुन	कर्क	सिंह	कन्या
तुला	वृश्चिक	धनु	मकर	कुम्भ	मीन

मेष:- - किसी श्रेष्ठजन के प्यार से मन प्रसन्न होगा। किसी की कटु वाणी मन को दुखित कर सकती है। उच्च महत्वकांशाएं व्यावसायिक क्षेत्र में अधिक परिश्रम के लिए प्रेरित करेंगी। आलस्य कर्तव्य न करें।

बृष्टभ- :- भौतिक महत्वकांशाएं अभाव का एहसास कराएंगी। परिजनों से कुछ भावनात्मक अपेक्षाएं कठिकारी हो सकती हैं। अच्छी योजनाओं द्वारा महत्वपूर्ण कार्यों को समयानुकूल पूर्ण करें।

मिथुन:- - भावनाओं पर नियतप्ररख अपने दायित्वों के प्रति सजग होना प्रगति का सूचक है। बचकाना स्वभाव महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एकाग्रता का अभाव पैदा करेगा। शिक्षा-प्रतियोगिता में परिश्रम का लाभ मिलेगा।

कर्क:- - महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां अपनी पूर्ति हेतु मन पर दबाव बनाएंगी। कुछ नयी आकांक्षाएं मन पर प्रभावी होंगी। भौतिक-सुख साधन में व्यय संभव। परिजनों से किसी प्रकार की शिकायत पर खुलकर बात करें।

सिंह:- - भावना से उद्भेदित मन निकट संबंधों के सुख-दुख के प्रति चिंतित होगा। पूर्वाग्रहवश संबंधियों के प्रति नकारात्मकता को न पालें। भविष्य संबंधों कुछ चिंताएं मन में नकारात्मक विचार ला सकती हैं।

कन्या:- - नये संबंधों में प्रगाढ़ा बढ़ेगी। पारिवारिक वातावरण सुखद व उत्साहपूर्ण होगा। जीविका क्षेत्र में मन अर्थिक सुदृढ़ा हेतु प्रयत्नशील होगा। रोजगार में व्यस्तता रहेगी किंतु जरूरी कार्य समय से पूर्ण करें।

तुला:- - कुछ नयी अभिलाषाएं आपको उत्साहित करेंगी। शासन-सत्ता की दिशा में केंद्रित लोगों को लाभ के अवसर प्राप्त होगे। किसी महत्वपूर्ण दायित्व की पूर्ति हेतु समुचित व्यवस्था हेतु मन चिंतित होगा।

वृश्चिक:- - किसी पुराने संबंध के प्रति विशेष निकटता की अनुभूति करेंगे। क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां अर्थिक सुदृढ़ता हेतु प्रेरित करेंगी। भावनाप्रधान मन रिश्तों से सहज ही प्रभावित हो जाता है।

धनु:- - रोजगार क्षेत्र में आपकी महत्वपूर्ण योजनाएं सार्थक होती हुई नजर आएंगी। श्रेष्ठजनों से नजदीकियां पैदा होंगी। व्यावसायिक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। कुछ प्रबल इच्छाएं आपको उद्भेदित करेंगी।

मकर:- - सामाजिक गतिविधियों में आपकी क्रियाशीलता बढ़ेगी। अच्छी भावनात्मक अभिव्यक्ति से संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा।

कुंभ:- - पुरानी समस्याओं को हल कर सुख की अनुभूति करेंगे। शासन-सत्ता से जुड़े लोगों का लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। पूजा-पाठ में पूरा दिन मन केंद्रित होगा। नये दायित्वों की पूर्ति होगी।

मीन:- - पिता के सहयोग से मुश्किल दिनों में राहत मिलेगी। बालसुलभता व असंयमित शब्दों का प्रयोग संबंधों में कटुता लाएगा। आकस्मिक नई आशंकाओं से प्रभावित मन कोई गलत निर्णय ले सकता है।

का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस समय वे लिखे गए थे। हम इन महाकाव्यों से उस समय के समाज के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। रामायण भारत में ही नहीं, बरन श्रीलंका, थाईलैंड, बाली और सुमात्रा सहित एशिया के कई देशों में अत्यंत लोकप्रिय हैं। रामायण के कई अलग-अलग संस्करण हैं। रामायण के मूल लेखक वाल्मीकि थे। गोस्वामी तुलसीदास ने जनभाषा अवधी में उसका अनुवाद कर उसे आम जनता तक पहुंचाया। सोलहवीं सदी से रामायण उत्तर भारत की जन संस्कृति का हिस्सा बनी हुई है। भगवान राम की वह कथा जो हिन्दू राष्ट्रवादियों को प्रिय है, इस कथा के कई अलग-अलग पाठों में से एक है। पौला रिचमेन की पुस्तक मेनी रामायन्स (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस), भगवान राम की कहानी के अलग-अलग संस्करणों के बारे में बताती है। इसी तर्ज पर ए.के. रामानुजन ने एक लेख लिखा था जिसका शीर्षक था-‘श्री हन्देड रामायंस फ़ाइब एंजामापिल्स एंड श्री थॉट्स ऑन ट्रांसलेशन।’ यह अत्यंत अर्थपूर्ण लेख दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का हिस्सा था। मगर बाद में एबीवीपी के विरोध के कारण इसे हटा दिया गया। हिन्दू राष्ट्रवादी रामकथा के एक विशिष्ट संस्करण को बढ़ावा देना चाहते हैं। रामानुजन बताते हैं कि इस कथा के कई स्वरूप हैं-जैन और बौद्ध स्वरूप हैं, और महिलाओं का संस्करण भी है, जिसकी लेखिका आंध्रप्रदेश की रंगनायकम्मा है। आदिवासियों की अपनी रामकथा है। अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक हिन्दू धर्म की पहेलिया में हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया है कि राम ने शम्बूक की केवल इसलिए हत्या कर दी थी क्योंकि वह शूद्र होते हुए भी तपस्या कर रहा था। इसी तरह, राम ने छुपकर और पीछे से वार कर बाली को मार दिया था। बाली कुछ पिछड़ी जातियां ही श्रद्धा के पात्र हैं। कहा जाता है-इडा पीडा जावो, बवीचे राज्य येवो (हमरे दुरुख और तकलीफें खत्म हों और बाली का राज फिर से कायम हो।) अम्बेडकर राम की इसलिए भी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं क्योंकि राम ने मात्र इसलिए सीता को जंगल में छोड़ दिया था क्योंकि उहें अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था। पेरियार भी द्रविड़ों पर आर्य संस्कृत लादने के लिए राम की आलोचना करते हैं। ठीक-ठीक क्या हुआ था यह साफनहीं है मगर यह महाकाव्य हमें उस काल के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें बताता है। उसी तरह महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित विश्व की सबसे लम्जी कविता महाभारत भी हमें उस युग में झांकने का मौका देती है। ये दोनों ग्रन्थ ज्ञान के स्रोत हैं। मगर उन्हें इतिहास के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल करना एक अलग मसला है, जिसका सम्बन्ध हिन्दू राष्ट्रवाद से ज्यादा और विद्यार्थियों को इतिहास के सच से परिचित करवाना कम है। यह भी कहा गया है कि पाठ्यपुस्तकों में इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाए। ऐसा बताया जा रहा है कि चूंकि हमारे देश को इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया था अतः वह गुलामी का प्रतीक है। इस तथ्य को जानबूझकर छुपाया जा रहा है कि हमारे देश के लिए इंडिया से मिलते-जुलते शब्दों का प्रयोग अंग्रेजों के भारत आने से बहुत पहले से हो रहा है। इसा पूर्व 303 में मगधनीज ने इस देश को इंडिका बताया था। सिन्धु नदी के नाम से जुड़े हुए शब्द भी लम्जे समय से इस्तेमाल हो रहे हैं। हमारे संविधान में प्रयुक्त वाक्यांश भारत देट इन इंडिया का कोई जवाब नहीं है। मगर हिन्दू राष्ट्रवादी एंजेडा के चलते इंडिया शब्द उन्हें असहज करता है वे भारत के इतिहास को नए सिरे से कालखंडों में विभाजित करना चाहते हैं। इतिहास के सबसे पुराने कालखंड, जिसे अंग्रेज हिन्दूकाल कहते हैं, को वे क्लासिक (श्रेष्ठ या उत्कृष्ट) काल कहना चाहते हैं। उद्देश्य है इस कालखंड में प्रचलित मूलों को हमारे समाज के लिए आदर्श निरूपित करना। ये मूल्य, जो मनुस्मृति में वर्णित हैं, वही हैं जिनके विरुद्ध अम्बेडकर ने विद्रोह का झंडा उठाया था और मनुस्मृति का दहन किया था। आज यूजीसी और एनसीईआरटी का मार्गदर्शक केवल और केवल हिन्दू राष्ट्रवादी एंजेडा है। भारतीय संविधान के मूल्यों से उन्हें कोई लेनदेना नहीं है।-राम पुनियानी

